सम्पादकीय

सामी साम्प्रदायों के बढ़ने से क्या होता है ?

डा. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

पिछले दिनों (27-28 जून) हिमाचल रिसर्च इस्टीच्यूट की और से चण्डीगढ़ में ,भारत में अल्पसंख्यक वाद के सामाजिक सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी प्रभावों पर एक दो दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत से वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकवाद को अलग-अलग मानना चाहिए। अल्पसंख्यक शब्द शुद्ध रूप से गणनात्मक है और इस सापेक्ष शब्द का आधार कोई भी कारक हो सकता है। उद्धाहरण के लिए भाषा, साम्प्रदाय, भौगोलिक क्षेत्र या फिर अन्य कोई भी कारक। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में पंजाबी भाषी भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, इसी प्रकार चीन में हंगरी के लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं । उसी प्रकार जिस प्रकार ईरान में आरमीनियाई अल्पसंख्यक हैं । परन्तु इसके विपरीत अल्पसंख्यकवाद एक मानसिकता का नाम है जो किसी भी दूसरे को सहन नहीं करती। यह मानसिकता सामी सम्प्रदायों यथा इस्लाम और ईसाइयत। इस्लाम के मानने वालों की संख्या जहाँ जहाँ बढ़ती है वहाँ वहाँ दूसरे सम्प्रदायों के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। सामी सम्प्रदायों की एक दूसरी विशेषता भी है कि वे अपने सम्प्रदाय के किसी सदस्य को किसी दूसरे सम्प्रदाय में जाने की अनुमति नहीं देते । इसके विपरीत भारतीय सम्प्रदायों की स्थिति इसके विपरीत है। प्रसिद्घ पत्रकार ए.जे. अकबर ने ठीक ही कहा है कि भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष नहीं है कि मुसलमान ऐसा चाहते हैं । बल्कि भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष है क्योंकि हिन्दी स्वभाव और संस्कार से ही पंथ निरपेक्ष होते हैं ।

इस पृष्ठभूमि में कश्मीर में इस्लाम को मानने वाले जो आचरण कर रहे हैं, उसे समझना और भी आसान हो जायेगा। कश्मीर से लगभग सभी हिन्दु और सिखों को निकाल दिया गया है । लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत संख्या में कुछ लोग वहाँ तमाम दिक्कतों के बावजूद रह रहें हैं । अब अपने अन्तिम अभियान में तालिबानी मानसिकता उन सभी को कश्मीर से निकालने पर तुली हुई है। श्रीनगर में सिखों की दुकानों और घरों को जलाया जा रहा है और उन्हें कश्मीर छोड़ने की चेतावनी दी जा रही है। जहाँ भी सामी सम्प्रदाय को मानने वालों की संख्या बढ़ती है वहीं भारतीय सम्प्रदायों को मानने वाले लोग संकट में पढ जाते हैं। कश्मीर में हिन्दु सिखें के साथ यही हो रहा है । दरअसल पाकिस्तान के बनने का भी यही मुख्य कारण था। देश के जिस हिस्से में इस्लाम को मानने वालों की संख्या बढ़ी, उसी हिस्से ने देश में रहने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं देश से अलग होकर अपने हिस्से से उन सभी लोगों को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जो लोग भारतीय सम्प्रदायों में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि पाकिस्तान में विभाजन के बाद हिन्दु सिखों की संख्या नग्णय रह गई जबकि भारत में इस्लाम को मानने वालों की संख्या 15 प्रतिशत है और वह दिन प्रतिदिन बड़ रही है। भारत में किसी भी व्यकित या दल ने कभी यह मांग नहीं की कि पाकिस्तान की तरह मुसलमानों को यहाँ से निष्काषित कर दिया जाये । इतना ही नहीं उन्हें अन्य सभी नागरिकों की तरह वे तमाम सुविधाए उपलब्ध हैं जो अन्य भारतीयों को हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान में तालिबानी मानसिकता हिन्दु और सिखों से, उनकी आस्था के आधार पर, जजिया टेक्स वसूल कर रही है।

श्रीनगर में सिखों को जो लूटा जा रहा है, उन्हें घाटी से भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसका कारण इस्लामी मानसिकता हो सकती है, परन्तु प्रश्न यह है कि भारत की पंथ निरपेक्ष सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। क्या सरकार मानती है कि हिन्दुओं और सिखों को कश्मीर में रहने का अधिकार है ? यदि ऐसा मानती है तो इस अधिकार की सुरक्षा के लिए मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं ? हो सकता है कि उनका सारा समय सच्चर कमेटियों और रंगनाथ मिश्रा आयोगों में ही निकल जाता हो लेकिन राजधर्म का पालन तो उन्हें उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार वे दूसरों को पालन करने की नसीहत देते हैं । ●